

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 के दायरे का वस्तुतः कथित

प्रलिस के लिये:

अनुच्छेद 19 का दायरा, सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकार

मेन्स के लिये:

महत्त्वपूर्ण नरिणय, मौलिक अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने नरिणय सुनाया है कि [अनुच्छेद 19\(2\)](#) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार को राज्य या उसके साधनों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है।

- न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि [अनुच्छेद 19\(1\)\(A\)](#) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार को [अनुच्छेद 19\(2\)](#) में पहले से नरिधारित कथित गए आधारों के अलावा किसी भी अतिरिक्त आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 19:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है और आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है।
 - भारतीय संविधान, 1949 का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, जो इस प्रकार हैं:
 - वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
 - शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार।
 - संगम या संघ बनाने का अधिकार।
 - भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार।
 - भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास का अधिकार।
 - वलिोपति
 - व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार।
 - भारतीय संविधान, 1949 का अनुच्छेद 19(2):
 - खंड (1) का उपखंड (a) किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा या राज्य को कोई भी कानून बनाने से नहीं रोकेगा, [हालाँकि उक्त उपखंड प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता और अखंडता के संदर्भ में उचित प्रतिबंध लगाता है](#) जैसे- राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या हिसा के लिये उकसाने के संबंध में।
- कुछ मौलिक अधिकार जैसे- [अस्पृश्यता](#), [तस्करी](#) और [बंधुआ मजदूरी](#) पर रोक लगाने वाले अधिकार स्पष्ट रूप से राज्य और अन्य व्यक्तियों दोनों के खिलाफ हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ:

- नजि संस्थाओं के खिलाफ अधिकार:
 - यह व्याख्या राज्य पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व डालती है कि नजि संस्थाएँ भी संविधानिक मानदंडों का पालन करती हैं।
 - यह कई संविधानिक कानूनी संभावनाएँ प्रदान करता है, जैसे कि नजि डॉक्टर के खिलाफ गोपनीयता के अधिकार को लागू करना या नजि सोशल मीडिया फर्म के खिलाफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करना।
- न्यायालय के पूर्व फैसलों का संदर्भ:
 - न्यायालय ने [पुट्टासवामी मामले](#) में वर्ष 2017 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें नौ न्यायाधीशों की बेंच ने सर्वसम्मति [सेनजिता को मौलिक अधिकार](#) के रूप में बरकरार रखा था।

- सरकार ने तर्क दिया कि नजिता एक ऐसा अधिकार है जिससे अन्य नागरिकों के खिलाफ लागू किया जा सकता है, इसलिये इसे राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

■ अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण:

- न्यायालय ने अन्य देशों की कानूनी प्रणालियों को देखते हुए यूरोपीय न्यायालयों के साथ अमेरिकी दृष्टिकोण की तुलना की।
- अमेरिकी कानून में "ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण" से "कषैतजि दृष्टिकोण" में बदलाव का एक उदाहरण न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम सुलविन मामले में सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय है, जिसमें पाया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ मानहानि कानून संबंधी राज्य का आवेदन भाषण और अभवियक्तकी स्वतंत्रता की संवधान की गारंटी के साथ असंगत था।
- जब अधिकारों को ऊर्ध्वाधर (Vertically) रूप से लागू किया जाता है, तो उनका उपयोग केवल सरकार के वरिद्ध ही किया जा सकता है; कषैतजि (Horizontally) रूप से लागू होने पर उनका उपयोग अन्य नागरिकों के वरिद्ध भी किया जा सकता है।
 - उदाहरण के लिये एक नागरिक किसी नजि कंपनी के खिलाफ जीवन के अधिकार के कषैतजि (Horizontally) आवेदन के तहत प्रदूषण उत्पन्न करने के लिये मुकदमा दायर कर सकता है, जो कि स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन होगा।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????????:

प्रश्न. भारत के संवधान के कसि अनुच्छेद के तहत 'नजिता का अधिकार' संरक्षति है? (2021)

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

प्रश्न. नजिता के अधिकार को जीवन और वयक्तगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरकि भाग के रूप में संरक्षति किया गया है। भारत के संवधान में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा उपर्युक्त वाक्य को सही एवं उचित रूप से लागू करता है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 और संवधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान।
- (b) अनुच्छेद 17 और भाग IV में राज्य नीति के नदिशक सदिधांत।
- (c) अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रता।
- (d) अनुच्छेद 24 और संवधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान।

उत्तर: (c)

??????????:

प्रश्न. नजिता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरे की जाँच कीजिये। (2017)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस